RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 20 NOVEMBER TO 26 NOVEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 13 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

1 दिसंबर से FASTag लगाना जरूरी
Page 2

ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन ट्रेड पर केंद्र बनाएगा पॉलिसी
Page 3

न्याय के देवता शनि को इस तरह करें खुश
Page 6

editoria!

तनख्वाह का दिन

केंद्र सरकार फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 'वन नेशन, वन पे डे' लागू करने पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था के लागू होने से हर सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन ही सैलरी मिला करेगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को सेंट्रल असोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्यॉरिटी इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'सिक्यॉरिटी लीडरशिप समिट-2019' को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इससे संबंधित कानून जल्द से तैयार होकर पास हो जाए। देश भर में एक दिन वेतन दिए जाने से नौकरीशुदा तबके को काफी राहत मिलेगी। अभी कई क्षेत्रों में वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितता रहती है। इससे वर्कर्स को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। वे अपने रोजमर्रा के खर्च के बारे में कई फैसले लेने से हिचकते हैं। यह आर्थिक असुरक्षा उनके कामकाज पर असर डालती है। कुछ कंपनियों के वर्कर्स में इस बात को लेकर असंतोष रहता है कि उनके यहां समय पर वेतन नहीं मिलता, जबकि कई जगहों पर सही समय पर सैलरी मिल जाती है। इसका भी काम पर असर पड़ता है। जब वेतन का दिन निर्धारित हो जाएगा तो वर्कर के भीतर एक तरह की सुरक्षा रहेगी। वेतन को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। वह अपने खर्च को लेकर तात्कालिक ही नहीं, दूरगामी योजना भी बना सकता है। वह बचत या निवेश के बारे में भी सोच सकता है। जब इस बारे में कानून बन जाएगा तो कंपनियां भी सैलरी देने में कोताही नहीं कर पाएंगी। कंपनी प्रबंधन पर इसका एक दबाव बना रहेगा। निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण पहलकदमी होगी। इस कानून को जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। एक लोककल्याणकारी राज्य में जरूरी है कि वेतन में बहुत ज्यादा असमानता न हो। हर मजदूर को इतना वेतन जरूर मिले कि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके अलावा उसे तमाम बुनियादी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। मोदी सरकार इसे लेकर सचेत है। संतोष गंगवार के अनुसार सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि मजदूरों की जिंदगी में सुधार हो सके। इसके लिए सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑन वेजेज को लागू करने की भी तैयारी में है। संसद से कोड ऑन वेजेज को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके नियमों पर काम चल रहा है। हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड को लोकसभा में इसी साल जुलाई में पेश किया गया था। यह कोड 13 श्रम कानूनों को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कई और प्रावधान भी जोड़े गए हैं। मसलन हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालाना फ्री मेडिकल चेकअप जैसे सुविधाएं देने की बातें इसमें शामिल की गई हैं। इन सुधारों से देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आएगा।

प्लास्टीविजन प्रदर्शनी का इंदौर में रोड शो संपन्न

कार्यक्रम की जानकारी मिडिया के साथ साझा करते आयोजक गण

प्लास्टिक उद्योगों को हर संभव सहयोग करेंगे- श्री कोरी

इंदौर।आईपीटी नेटवर्क

देश में औद्योगिक गति को बढावा देने में औद्योगिक प्रदर्शनी और एक्सपो का बडा योगदान है। ऐसे आयोजन में कंपनियों को अपने उत्पादों, मशीन और तकनीकों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। उद्योगों के लिए नई तकनीक और शोध से रूबरू होने का अवसर भी मिलता है। प्लास्टिक इंडिया 2020 प्रदर्शनी, ऑल इंडिया प्लास्टिक निर्माताओं एसोसिएशन द्वारा आयोजित बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में 16 से 20 जनवरी 2020 के बीच आयोजित की जाएगी।कार्यक्रम संयोजक और इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि जनवरी 2020 में आयोजित प्लास्टिविजन प्लास्टिक प्रदर्शनी का यह 11 वां संस्करण, जिसे दुनिया की शीर्ष 5 प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है। इस आयोजन में मप्र के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए इंदौर में लांच इंवेंट आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया। आयोजन इंदौर की सयाजी होटल में किया गया था। कार्यक्रम में सीपेट भोपाल, ग्वालियर, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र सहित अन्य शासकीय विभाग के अधिकारी भी आमंत्रित थे।आईपीपीएफ अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथी मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री आर एस कोरी थे। आयोजन मे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, एमएसएमई इंदौर, सहित इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, एआईएमपी, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, लघु उद्योग भारती सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी और विभिन्न कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होने बताया कि कार्यक्रम में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मुंबई के पदाधिकारी श्री हरेंन संघवी, श्री ऋतुराज और हरीश धर्मासी भी शामिल हुए।

(शेष पृष्ठ 4+5 पर)

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के कार्यकलापों की जानकारी देते अध्यक्ष श्री सचिन बंसल

ओपेक पर कम हो रही भारत की निर्भरता अक्टूबर में केवल 73 फीसदी तेल आयात

नई दिल्ली। एजेंसी

ओपेक से भारत के तेल आयात में अक्टूबर महीने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि अब तेल आयात के लिए भारत की ओपेक से निर्भरता कम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक महीने भारत ने कुल आयात का 73 प्रतिशत ही ओपेक से आयात किया। टैंकर डेटा के मुताबिक 2011 के बाद एक महीने में यह सबसे कम आयात है। आम तौर पर भारत कुल जरूरत का 80 प्रतिशत ओपेक देशों से ही आयात करता है। लोकल रिफाइनर अपग्रेड होने के साथ भारत अब इनसे भी सस्ता कच्चा तेल खरीदने लगा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अक्टूबर में भारत 45.6 लाख बैरल तेल का रोज आयात किया जो कि पिछले साल के मुकाबले 3.3 फीसदी कम है। सितंबर में भारत ने कुल आयात का 81 प्रतिशत ओपेक से आयात किया था। इसके अलावा सितंबर महीने में सऊदी के ऑइल प्लांट पर हुए ड्रोन अटैक की वजह से उत्पादन कम हो गया था।

●भारत ने अक्टूबर महीने में ओपेक से 11 साल में सबसे कम तेल आयात किया ●अब ओपेक पर भारत की निर्भरता कम हो गई है और कई लोकल रिफाइनरों से भी तेल खरीदा जा रहा है ●इसके अलावा अक्टूबर में ईंधन की मांग में भी कमी दर्ज की गई ●वहीं भारत ने सऊदी अरब के बजाय अब इराक और नाइजीरिया को प्राथमिकता देनी शुरू की है

इसके बाद इराक ने सबसे ज्यादा तेल निर्यात करना शुरू किया। जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब ने तेल की कीमतें बढ़ा दीं और इस वजह से आयातक देशों ने इराक की तरफ रुख कर लिया। सऊदी से बढ़ी हुई कीमतों पर तेल खरीदने की जगह भारत ने नाइजीरिया से आयात करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। अक्टूबर में नाइजीरिया कुवैत और मेक्सिको के बाद तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से भी रेकॉर्ड आयात किया। प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस ने अमेरिका से तीन टैंकर कार्गो मंगवाए। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में ईंधन की मांग में भी 1.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा डीजल की खपत तीन साल में सबसे कम अक्टूबर के महीने में हुई।

6 महीने में बैंकों के साथ 95,700 करोड़ का फ्रॉड

3.38 लाख खाते हुए बंद

अप्रैल से सितंबर के बीच धोखाधड़ी के 5,743 मामले

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकों के साथ फ्रॉड कम नहीं हुआ है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया है कि सिर्फ 6 महीने में बैंकों के साथ 95,700 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। वित्त मंत्री ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यसभा में कहा, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 की अवधि में 95,760.49 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 5,743 मामले हुए।

इसके साथ ही बताया गया कि कि 3 लाख से अधिक निष्क्रिय कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। इसी के तहत 3.38 लाख निष्क्रिय कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई है।

बैंकों का बढ़ा एनपीए

निर्मला सीतारमण का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीएसयू या निजी बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ गया है। दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक को मुनाफे के बावजूद नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बढ़ा है। इंडसइंड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 30 सितंबर, 2019 तक बैंक का एनपीए कुल कर्ज का 2.19 फीसदी है। एक साल पहले इसी अवधि में एनपीए 1.09 फीसदी था। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक के एनपीए में 1.11 फीसदी का इजाफा हुआ है।

वहीं कोटक बैंक के भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनपीए 2.17 फीसदी पर है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1.91 फीसदी था। इसी तरह कर्नाटक बैंक का एनपीए उसके कुल कर्ज का 4.78 फीसदी रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 4.66 फीसदी था। हालांकि एक्सिस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घाटे से जूझना पड़ा है। लेकिन बैंक की कर्ज में फंसी राशि यानी एनपीए सितंबर 2019 में घटकर 5.03 फीसदी रह गया। इसी तरह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और एचडीएफसी बैंक के भी एनपीए में कमी आई है।

भारत के लिए तेल की कीमत, वैश्विक पूंजी प्रवाह में उतार चढ़ा का खतरा : पूर्व आरबीआई गवर्नर

हैदराबाद। एजेंसी

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि चीन, ईरान और पश्चिम एशिया के इर्द-गिर्द होने वाली गतिविधियों से कच्चे तेल की कीमत और पूंजी प्रवाह में भारती उतार चढाव का डर है और भारत के लिए ये दोनों ही बातें खतरनाक हैं। अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन काम्प्लेक्स च्वाइसेस (आईएएससीसी) द्वारा आयोजित यहां आयोजित एक कार्यक्रम में रेड्डी ने कहा कि दुनिया अब नए तरह से दो ध्रुवीय हो गयी है। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई होने के बावजूद अलग अलग धुवों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया-ईरान या चीन-अमेरिका तनाजे से कम-से-कम अल्पकाल में दो प्रकार के वित्तीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, तेल की कीमतों का झटका लग सकता है और दूसरा पहलू पूंजी प्रवाह का है। इन सबसे जो देश सर्वाधिक प्रभावित होगा, वह भारत है। रेड्डी ने कहा, "हम पूंजी खाते के झटके की दृष्टि से हमारी स्थिति ज्यादा दुर्बल है।"उन्होंने कहा कि तीन आर्थिक चुनौतियां हैं...जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या स्वरूप में भिन्नता और प्रौद्योगिकी। ये समस्याएं वैश्विक हैं और सहयोग तथा समन्वित प्रयास के जरिये ही इसका समाधान किया जा सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौती है जहां सामूहिक रूप से कार्रवाई अपरिहार्य है लेकिन यह धीरे-धीरे कठिन होता जा रहा है।उन्होंने कहा कि जनसंख्या के स्वरूप में भिन्नता से वृहत आर्थिक संतुलन प्रभावित हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जनसंख्या का आव्रजन एक विवशता होता जा रहा है। रेड्डी ने कहा कि आव्रजन के प्रबंधन को लेकर अबतक कोई समझौता नहीं है जबकि ऐसा करना जरूरी है। पूंजी वैश्विक है लेकिन श्रम का मामला राष्ट्रियता से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में वैश्विक संतुलन को प्रभावित करेगा क्योंकि प्रौद्योगिकी प्रगति इतनी तेज है कि ....संस्थाएं इन बदलावों से पार पाने में कठिनाई महसूस कर रही हैं।

पनबिजली उत्पादन की वृद्धि दर 16%

नयी दिल्ली। एजेंसी

बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि देश में पनबिजली उत्पादन में चालू वित्त वर्ष में अब तक 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है और यह पनबिली क्षेत्र की पांच साल की सबसे ऊची वृद्धि दर है। उन्होंने कहा कि कुल बिजली उत्पादन में कोयला और दूसरे खनिज ईंधनों के इतर वैकल्पिक स्रोतों से उत्पादित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ी है। सिंह ने कहा कि देश में कुल बिजली उत्पादन जून 2019 को समाप्त तिमाही 7.4 प्रतिशत और जुलाई माह में 6.7 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर महीने में बिजली उत्पादन पहले के स्तर पर बना रहा लेकिन उसके बाद के महीने में इसमें कमी आयी क्यों कि देश के कई भागों में अत्यधिक बारिश होने के कारण एयर कंडीशन और सिंचाई के लिये बिजली की मांग कम हुई। मंत्री ने कहा, "अप्रैल-अक्टूबर के दौरान बिजली उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अक्टूबर महीने में बिजली उत्पादन में कमी आयी क्योंकि अत्यधिक बारिश से एयर कंडीशन के लिये बिजली की जरूरत कम हुई। लेकिन यह कहना कि इसका कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी है, बेतुका है।" उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस अपने हिसाब से आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की नरमी का दुष्प्रचार कर रही है। सिंह ने कहा, "यह सही है कि अक्टूबर में बिजली उत्पादन करीब 13 प्रतिशत घटा। लेकिन यह सिर्फ परंपरागत स्रोतों से उत्पादित बिजली के मामले में हुआ। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी शामिल नहीं है। इस महीने में सौर बिजली उत्पादन बढ़ा और पनबिजली उत्पादन में भी वृद्धि हुई।" उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान पनबिजली उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई (करीब 96 अरब यूनिट) जो पांच साल की सर्वाधिक वृद्धि है। देश में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 27.25 प्रतिशत है। सिंह ने कहा कि एयर कंडीशन के लिये ऊर्जा मांग नहीं होने के बावजूद नवंबर महीने में बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।

रजत भार्गव पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र पर समिति के प्रमुख नियुक्त

अमरावती। एजेंसी

केंद्र ने आंध्र प्रदेश के नौकरशाह रजत भार्गव को पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) पर उच्चस्तरीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। यह समिति क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उपाय सुझाएगी। भार्गव आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं संरचना विभाग में प्रमुख सचिव हैं। उनकी नियुक्ति केंद्रीय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय रसायन एवं पेट्रोरसायन सचिव पी राघवेंद्र राव की अगुवाई में मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में पीसीपीआईआर नीति में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया। यह नीति 2007 से लागू है। बैठक में भार्गव की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया गया। अधिकारी ने कहा, "यह समिति तमिलनाडु, ओड़िशा और गुजरात के प्रमुख सचिवों, उद्योग संघों और अन्य अंशधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद एक पखवाड़े में अपनी रिपोर्ट देगी।" पिछले कुछ साल से सरकार विभिन्न मुद्दों को हल कर पीसीपीआईआर में निवेश आकर्षित करने के लिए नीति में बदलाव पर विचार कर रही है।

1 दिसंबर से FASTag लगाना जरूरी, नगद में देना होगा दोगुना टोल टैक्स

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

अगले महीने यानी 1 दिसंबर से सरकार हाइवे पर टोल चुकाने के लिए FASTag को अनिवार्य करने जा रही है। सरकार 100 प्रतिशत टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहती है। 1 दिसंबर से देशभर के नैशनल हाइवे के टोल प्लाजा सभी लेन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे, ताकि लोगों पर टोल प्लाजा पर बेवजह समय न गंवाना पड़े। क्या है FASTag?यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगेगा, जो बैंक अकाउंट या नैशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेमेंट वॉलिट से जुड़ा होगा। इससे गाड़ी मालिकों को टोल प्लाजा से गुजरते रुकने की जरूरत नहीं होगी और रकम अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। नैशनल हाइवेज फी (रेट और कलेक्शन निर्धारण) रूल्स, 2008 के मुताबिक, किसी टोल प्लाजा में FASTag लेन FASTag यूजर्स की आवाजाही के लिए खासतौर पर रिजर्व है। अगर कोई गाड़ी मालिक बगैर

FASTag के FASTag लेन से गुजरता है तो उसे दोगुनी फीस वसूली जाएगी।

कहां से ले सकते हैं Fastag?

आप किसी भी सकारी बैंक से फास्टैग स्टीकर ऑफलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करके भी फास्टैग मंगवाया जा सकता है। इसके लिए आपको बैंक की फास्टैग ऐप्लिकेशन वेबसाइट पर जाना होगा और डीटेल भरकर आवेदन करना होगा। जब आपका फास्टैग अकाउंट बन जाएगा तो इसे मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इसे आप अपने बैंक अकाउंट से रिचार्ज कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा Fastag?

मंत्रालय ने सिस्टम में बदलाव की निगरानी और नैशनल हाइवेज अथॉरिटी (NHAI) के साथ तालमेल बनाकर काम करने के लिए करने के लिए कई राज्यों में केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसका क्रियान्वयन NHAI ही कर रही है। ऊपर जिस अधिकारी का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि अधिकांश कमर्शल गाड़ियों ने पहले ही ईएफ्रैंड सिस्टम अपना लिया है। निजी कार मालिक अभी भी कैश टोलिंग से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, 'हम सभी टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को FASTags के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आखिर में FASTag को मोबाइल की तरह रिचार्ज करने की सहूलियत भी दे देंगे।'

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा 'डेटा संरक्षण विधेयक'

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक' को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह विधेयक लोगों की निजी जानकारियां उनकी मर्जी के बिना उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाएगा।प्रस्तावित विधेयक में लोगों की निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, "डेटा संरक्षण विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।" व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2018 का मसौदा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने डेटा संरक्षण से जुड़े मसलों पर सुझाव देने के लिए किया था। विधेयक में व्यक्तियों से जुड़ी निजी जानकारियों को देश से बाहर भेजने पर प्रतिबंध और कई शर्तें लगाने के साथ भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है। यह प्राधिकरण निजी जानकारियों के किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकेगा। विधेयक में डेटा संग्रह करने वाली किसी इकाई के नियमों का उल्लंघन करने पर उसके वैश्विक कारोबार (टर्नओवर) का चार प्रतिशत या 15 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इंडियन इंफोसेक कंसोर्टियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन जैन ने कहा कि यह विधेयक एक आम व्यक्ति की जानकारी का अन्यत्र उपयोग किए जाने पर सख्ती से नियंत्रण रखेगा। यह कंपनियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा जिससे कई बार किसी व्यक्ति की निजता में सेंध लगा दी जाती है।

ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन ट्रेड पर केंद्र बनाएगा पॉलिसी

नई दिल्ली। छोटी किराना दुकानों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने में मदद करने के लिए सरकार नैशनल रिटेल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। योजना के तहत रिटेलर्स को वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, वर्किंग कैपिटल के लिए सॉफ्ट लोन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।सरकारी अधिकारी नेबताया, 'एक नेशनल फ्रेमवर्क पर काम शुरू हुआ है, जिसे राज्य अपना सकते हैं।'

DPIIT ने स्टोर की संख्या बताने को कहा

रिटेल से जुड़े मामले राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। सभी राज्यों ने सेक्टर को लेकर अलग-अलग पॉलिसी अपना रखी है। फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड ने राज्यों से ऐसे स्टोर की संख्या बताने को कहा है।

जीडीपी में लोकल ट्रेड की 15% हिस्सेदारी

देश की 2.7 लाख करोड़ डॉलर की उअ्र में लोकल ट्रेड की 15 पर्सेंट हिस्सेदारी है। देश में छह करोड़ से अधिक बिजनस एंटरप्राइजेज हैं। अनुमान के मुताबिक, डोमेस्टिक ट्रेड से 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और यह आंकड़ा हर साल 15 पर्सेंट बढ़ रहा है। ज्यादातर राज्यों में दुकानों से जुड़े नियम हैं, जिनके तहत स्टोर को रजिस्टर किया जाता है। हर राज्य में रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, फीस और अन्य कायदे अलग हैं। कुछ राज्यों में सालाना तो कुछ में हर साल पर दुकानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

किराना दुकानों की लागत घटाएगी सरकार

सरकार नैशनल पॉलिसी के जरिए नियमों को आसान, समान और कम जटिल बनाने और किराना दुकानों पर कॉस्ट का भार घटाने की कोशिश कर रही है। सूत्र ने बताया कि फ्रेमवर्क में लाइफटाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट की सुविधा मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया, 'हम छोटे दुकानदारों की परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके लिए सॉफ्ट लोन, डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म जैसी सुविधाओं पर भी विचार कर रहे हैं।'

CAIT ने संभाला मोर्चा

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड (CAIT) के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, लगभग 65 पर्सेंट स्टोर ऐसे हैं, जिनका डिजिटलीकरण नहीं हुआ है। ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ रिटेलर्स की शिकायतों का मोर्चा ण्ष्ठ ने संभाला है। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हालांकि, ई-कॉमर्स फर्मों ने आरोपों को खारिज किया है।

राज्य बन सकते हैं कर्ज का गारंटर

नैशनल पॉलिसी के तहत सरकार और रिटेलर ग्रुप्स के बीच राज्य को कर्ज का गारंटर बनाने पर भी चर्चा हुई है। इससे बैंकों को दुकानदारों को कम ब्याज दर पर लोन देने में मदद मिलेगी। कर्ज देने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों में भी कटौती होगी। अधिकारी ने बताया कि DPIIT नैशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का दायरा भी बढ़ा रहा है। रिटेल कम्युनिटी के भले के लिए सरकार ने पहले ही दुकानदारों, रिटेल ट्रेडर्स और स्वरोजगार करने वालों के लिए पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 60 साल की उम्र होने पर उन्हें 3,000 रुपये की मंथली पेंशन मिलेगी।

नोटबंदी का खौफ?

आयकर विभाग की रेड में मिलने वाले 2,000 के नोटों में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। आम तौर पर आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों के छापे में पहले कालाधन जमा करने वालों के पास से बड़े नोट निकला करते थे लेकिन अब यह ट्रेंड बदल रहा है। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद अवैध धन जमा करने वालों के मन में खौफ बैठ गया है कि पता नहीं कब सरकार बड़े नोटों को बंद कर दे। इस सयम मार्केट में सबसे बड़ा नोट 2000 का है लेकिन सरकार के मुताबिक आयकर विभाग के छापों में बरामद रकम में 2,000 के नोट ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। गुरुवार को सरकार ने बताया कि 2017-18 में विभाग के छापे में बरामद रकम में 68 फीसदी नोट 2000 के थे जो कि इस साल गिरकर 43 फीसदी ही रहे गए हैं। अनुमान यह भी है कि 2,000 के नोटों की संख्या इसलिए भी कम हुई है क्योंकि रिजर्व बैंक ने इन नोटों का फ्लो घटा दिया है। इसके अलावा नोटबंदी का भी लोगों को डर लगा रहता है। अब अवैध धन जमा करने वाले लोग छोटे नोटों को प्राथमिकता देते हैं। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया, 'पिछले तीन वित्तीय वर्षों में रकम की बरामदगी को लेकर अध्ययन किया गया जिसमें पता चला है कि 2,000 के नोटों की बरामदगी लगातार घटी है। पिछले तीन साल में यह घटकर 67.9 फीसदी से 43.2 फीसदी हो गई है।' बता दें कि नोटबंदी में 1,000 और 5,00 के नोट बंद होने के बाद सबसे पहले नए 2,000 के नोट ही बाजार में आए थे। इससे पहले के छापों में सबसे ज्यादा नोट 1,000 के और फिर 5,00 के बरामद होते थे। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 में 2,000 के नोटों का फ्लो लगभग आधा हो गया। इस समय इन नोटों का फ्लो केवल 31 फीसदी रह गया है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक लगातार 2,000 के नोटों का फ्लो कम ही हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इन नोटों को बाजार में ज्यादा मात्रा में नहीं रहने देना चाहती।

सुब्रोस का गुजरात का विनिर्माण संयंत्र शुरू

नयी दिल्ली। वाहन कलपुर्जा कंपनी सुब्रोस के गुजरात के विनिर्माण संयंत्र का बुधवार को उद्घाटन किया गया। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि यह नया कारखाना गुजरात के अहमदाबाद जिले के तालुका मंडल के करसनपुरा गांव में लगाया गया है। सूचना में कहा गया है कि इस परियोजना का पहला चरण अब पूरा हो गया है। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों की मांग के अनुरूप वाहनों के एयरकंडीशनर के पुर्जों और इंजन कूलिंग मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस नए कारखाने से क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। कंपनी ने कहा है कि वह ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप नवोन्मेषी उत्पाद लाएगी।

ई-वे बिल और रजिस्ट्रेशन बचाने की होड़, पोर्टल ठप

GSTR-3B की लास्ट डेट आज, दो रिटर्न चूकने वालों का 21 से ट्रांसपोर्टेशन होगा बंद

नई दिल्ली। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों के खिलाफ कल से होने जा रहीं दो सख्त कार्रवाइयों से नॉन-फाइलर्स में अफरा-तफरा मची है। अक्टूबर महीने के मंथली रिटर्न उएऊ-3ँ की आखिरी तारीख 20 नवंबर से ऐन पहले फाइलिंग की होड़ से मंगलवार को जीएसटी पोर्टल स्लोडाउन का शिकार हो गया। देश भर से पोर्टल नहीं चलने की शिकायतें आती रहीं। टैक्सपेयर्स अब डेडलाइन 25 तक बढ़ाने की मांग करने लगे हैं।

जीएसटी कलेक्शन में तंगी से परेशान सरकार ने अब सख्ती के मूड में है। इसके लिए पहले रिटर्न नहीं भरने वालों की नकेल कसी जाएगी। 21 नवंबर से लागू होने जा रहे जीएसटी के रूल 138E के तहत लगातार दो टैक्स पीरियड का GSTR-3B नहीं भरने वालों का ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद ये कारोबारी ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाने के कारण 50 हजार रुपये से ज्यादा वैल्यू की माल ढुलाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी कार्रवाई के तहत जीएसटी के चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर ने सभी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि जिन कारोबारियों ने लगातार छह टैक्स पीरियड में रिटर्न नहीं भरा है, 25 नवंबर तक उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसल होने से जहां आगे हर तरह की कारोबारी गतिविधियां अवैध हो जाएंगी, वहीं दोबारा रजिस्ट्रेशन में काफी समय लग सकता है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी में रजिस्टर्ड करीब सवा करोड़ कारोबारियों में से औसतन 21 लाख रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं।

इन दो मुश्किलों से बचने के लिए नॉन-फाइलर्स में हलचल मची। यही कारण है कि मंथली 3ँ की डेडलाइन से एक दिन पहले सिस्टम पर लोड बढ़ गया। जीएसटी कंसल्टेंट सुधीर हालाखंडी ने बताया कि सुबह से फाइलिंग नहीं हो रही है। ऐसा तब है, जब वित्त सचिव ने तीन दिन पहले ही सिस्टम की समस्याएं नकारी थीं। सरकार को सबसे पहले जीएसटी सर्वर की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए।

सीए चिराग चौहान ने कहा कि मंथली रिटर्न की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बचा है और फाइलिंग ठप होना शर्म की बात है। हर महीने आखिरी दिनों में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। इस रिटर्न की अहमियत को देखते हुए डेडलाइन 25 नवंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए। इस साल जीएसटी कलेक्शन उम्मीद से काफी पीछे जा रहा है। अगस्त और सितंबर में कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले क्रमशः 4ञ और 5ञ गिरा था, जबकि पीक फेस्टिव सीजन वाले अक्टूबर में भी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से नीचे ही रहा। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि सरकार अब बहुत नरमी के मूड में नहीं है।

प्लास्टीविजन प्रदर्शनी

प्लास्टिविजन २०२० के कार्यक्रम को संबोधित करते इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल

आईपीपीएफ के अध्यक्ष सचिन बंसल, महासचिव राम किशोर राठी और कोषाध्यक्ष विकास बांगड, इपमा वेस्ट झोन प्रमोशन कमेटी के चैयरमैन श्री सुभाष चतुर्वेदी के साथ

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष सचिन बंसल और अन्य पदाधिकारियों के साथ

पत्रकारों को प्लास्टिविजन २०२० की जानकारी देते आईपीपीएफ अध्यक्ष सचिन बंसल

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोजन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री आरएस कोरी ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने और नियमों का पालन कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल हरसंभव मदद करेगा। नियम अनुसार चलने वाले उद्योगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी उद्योग लाइसेंस प्रक्रिया को पालन करें उसके लिए कैंप लगाकर मदद की जाएगी। मुंबई से आए श्री ऋतुराज जी ने ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्लास्टिविजन 2020 के आयोजन की खूबियां और जानकारी प्रस्तुत की जिसे उद्योगपतियों ने खूब सराहा। अतिथियों को श्री आरके माहेश्वरी ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव सचदेवा ने किया और आभार प्रदर्शन हरीश धर्मासी ने किया।कार्यक्रम में श्री अशोक जयसवाल श्री जमुना लाल शर्मा, श्री सुभाष चतुर्वेदी,श्री रामकिशोर राठी, श्री विकास बंगाड, श्री विवेक बंसल, संदीप ठाकुर सहित अनेक उद्योगपति मौजूद थे।

इस पांच दिवसीय प्रदर्शनी में 25 से अधिक देशों ने अपनी भागीदारी करेंगे। जो नई तकनीक और मशीनरी का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। इस अवधि के दौरान, कई तकनीकी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगें। आगंतुक और प्रदर्शक कृषि, सौर, स्वचालन, डाई और मोल्ड, अपशिष्ट प्रबंधन और 3 डी प्रिंटिंग में केंद्रित प्रदर्शकों के साथ 6 विशेष मंडपों में उत्पादों और सेवाओं को देख सकेंगे। उन्होने बताया कि 250,000 से अधिक व्यापार विजीटरों को आकर्षित करने के लिए 50 से अधिक रोड शो का आयोजन करके पूरे भारत में किया है।

प्लास्टिविजन २०२० के इंदौर लांच इवेंट का शुभारंभ करते मुख्य अतिथी श्री आरएस कोरी, सदस्य सचिव मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भोपाल

प्लास्टिविजन २०२० के प्रेजेंटेशन को देखते मुख्य अतिथी श्री आरएस कोरी, विशेष अतिथी अशोक जायसवाल, मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल इंदौर के आरओ आरके गुप्ता, एआईएमपी अध्यक्ष प्रमोद डफरिया और सचिव सुनिल व्यास

आयोजन में शामिल विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी और अधिकारी

मुंबई से आए मेहमन श्री हिरेन संघवी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते आईपीपीएफ कार्यकारिणी सदस्य और अध्यक्ष

का इंदौर में रोड शो संपन्न

प्लास्टिविजन २०२० के इंदौर लांच इवेंट के मंच पर बैठे सभी अतिथी और आयोजक सदस्य

मुंबई से आए प्लास्टिविजन २०२० के प्रमोशन टीम के सदस्य और आल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गण श्री ऋतुराज जी, श्री हरीश धर्मासी और श्री हिरेन संघवी

मुख्य अतिथी आरएस कोरी को स्मृति चिन्ह देते मप्र रिप्रोसेस ग्रेन्युअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आरके माहेश्वरी

प्लास्टिवेशन 2020 में प्रदर्शन क्यों ...

- 16 से 20 जनवरी 2020 तक आयोजित किए जाने वाले प्लास्टिक इंडिया 2020 का 11 वां संस्करण।
- 35 + प्लास्टिक खंडों से 1500 प्रदर्शक।
- 7 हॉल में 100,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैलने के लिए।
- 25 से अधिक देशों से भागीदारी
- शीर्ष 5 वैश्विक प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक।
- 250,000 से अधिक व्यापार आगंतुक
- विशाल नेटवर्किंग के अवसर।
- अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यावसायिक सम्मेलन के वक्ता
- मुंबई, भारत की वाणिज्यिक और वित्तीय राजधानी और कई प्लास्टिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विभिन्न एसएमई और एएई को घर में आयोजित किया जाना
- ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पर 11 केंद्रित थीम पवेलियन, इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्लास्टिक, मेडिकल प्लास्टिक, कृषि में प्लास्टिक, सौर ऊर्जा, डाई एन मोल्ड, ग्रीन पवेलियन आदि।
- भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 30-35 किलो वैश्विक खपत की तुलना में मात्र 9 किलो है।

विशेष अतिथी अशोक जायसवाल को स्मृति चिन्ह प्रदान करते श्री सुभाष चतुर्वेदी और हरीश धर्मासी

मुंबई से आए मेहमन श्री हिरेन संघवी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते आईपीपीएफ के श्री विवेक बंसल और अध्यक्ष सचिन बंसल

मुख्य अतिथी श्री आरएस कोरी के साथ आईपीपीए अध्यक्ष सचिन बंसल, सचिव रामकिशोर राठी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता, एआईएमपी अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, योगेश मेहता, दीपक भंडारी सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी

दिसंबर से बढ़ जाएगा आपका मोबाइल और इंटरनेल का बिल

इन कंपनियों ने किया दरें बढ़ाने का ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

आने वाले दिनों में आपका मोबाइल और इंटरनेट बिल बढ़ने जा रहा है। एयरटेल और वोडाफोन ने दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पहले से संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर में दूसरी कंपनियां भी ये रास्ता अख्तियार कर सकती हैं। एक तिमाही में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा उठाने वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने आखिरकार अपना बोझ ग्राहकों पर डालने का फ़ैसला किया है। यही रास्ता भारती एयरटेल भी ले रही है, जिसे पिछली तिमाही में 23,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है। नतीजा ये है कि एक दिसंबर से ये कंपनियां अपनी दरें बढ़ाने जा रही हैं। हालांकि फिलहाल वो बेहतर सुविधाओं का वादा भी कर रही हैं। दरों के बढ़ाए जाने के बारे में वोडाफोन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति सेक्टर को राहत देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। दरअसल पिछले महीने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है जिसमें टेलिकॉम आपरेटरों को करीब 92000 करोड़ की बकाया रकम सरकार को चुकाने का निर्देश दिया गया है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी ने कहा कि वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं। पहले ही वोडाफ़ोन ने ऐलान किया था कि दूसरी तिमाही में उसे 50921 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि इस तिमाही में एयरटेल को 23045 करोड़ का घाटा हुआ है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कुल घाटा बढ़कर 4.72 लाख करोड़ पहुंच गया है। वो चाहते हैं कि घाटा कम करने में सरकार लाइसेन्स फीस और स्पेक्ट्रम यूज़ेस चार्ज घटाए। साफ है संकट बड़ा है. टेलिकॉम सेक्टर पर कर्ज़ का बोझ बढ़कर 7.6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है।

देश में स्टेनलेस स्टील की प्रति व्यक्ति खपत बढ़कर 2.5 किलोग्राम हुई: आईएसएसडीए

नयी दिल्ली। देश में स्टेनलेस स्टील की प्रति व्यक्ति खपत बढ़कर 2.5 किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए) ने सोमवार को यह बात कही। एसोसिएशन ने बयान में कहा कि 2010 में स्टेनलेस स्टील की प्रति व्यक्ति खपत 1.2 किलोग्राम थी। यह 2019 में बढ़कर 2.5 किलोग्राम हो गई है। इस दौरान , खपत में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। बयान में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के हवाले से कहा गया है , ' देश में स्टेनलेस स्टील की मांग सालाना आधार पर 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह विश्व में सबसे अधिक है। स्टेनलेस स्टील की मांग सीधे आर्थिक वृद्धि से जुड़ी है। ' आईएसएसडीए के अध्यक्ष के . के . पाहुजा ने कहा कि एसोसिएशन ने नए स्टेनलेस स्टील के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

स्टेनलेस स्टील के लिए अब भारत सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। उन्होंने कहा कि 2.5 किलोग्राम खपत का लक्ष्य हासिल करने के साथ भारत महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है और उन देशों की सूची में शामिल हो गया है , जहां स्टेनलेस स्टील खपत में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। आईएसएसडीए ने कहा कि आसियान , जापान और कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते के कारण वहां के उत्पादों को आने में कम रुकावट से मांग - आपूर्ति की स्थिति खराब हुई है और इसका घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसोसिएशन ने कहा , ' एमएसएमई (सूक्ष्म , लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र में करीब आधे उद्योग सस्ते आयात से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा , स्टेनलेस स्टील कबाड़ और फेरो निकेल जैसे प्रमुख कच्चे माल की अधिक लागत भारतीय उत्पादों को कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। एसोसिएशन ने इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया है और घरेलू उद्योग की मुश्किलों को दूर करने पर काम कर रहा है।

किस राशि के लिए कौनसी धातु है श्रेष्ठ

ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बतलाए गए हैं जिनमें मूल ग्रह 7 होते हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ग्रहों के अनुसार ही हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं इसी कारण ग्रहों से संबंधित अलग-अलग धातुएं राशि के अनुसार बताई गई हैं । कुंडली में अगर कोई प्लेनेट अशुभ फल दे रहा हो तो उससे संबंधित उपाय करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती हैं। हमारे ग्रह दोषों को दूर करने का उपाय यह भी है कि हमें उस ग्रह एवं राशि से संबंधित धातु को धारण करना चाहिए जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए उस धातु की अंगूठी बनवाकर अपनी अंगुली में या फिर चैन बनवाकर अपने गले में या फिर ब्रेसलेट के रूप में अपने हाथों में धारण कर सकते हैं। किस राशि के लिए कौन सी धातु श्रेष्ठकर होती है ।

सोना: यह धातु मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि इस सोना धातु का कारक ग्रह गुरु है।

चांदी: यह धातु वृषभ, कर्क, तुला, राशि के व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है इस धातु का स्वामी चंद्रमा है।

लोहा: यह धातु मकर और कुंभ के जातकों के लिए अति उत्तम मानी गई है इन व्यक्तियों को लोहे की अंगूठी अपने मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। इस धातु के कारक ग्रह शनि देव है।

तांबा: यह धातु मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस धातु के स्वामी ग्रह सूर्य है।

पीतल: यह धातु सोने के समान ही मेष, सिंह,वृश्चिक धनु और मीन राशि के व्यक्तियों के लिए अति फलदायक है। इस धातु का कारक ग्रह गुरु हैं।

कांसा: यह एक मिश्रित धातु है यह बुध ग्रह से संबंधित धातु मानी जाती है मिथुन एवं कन्या राशि के जातकों के लिए यह अति श्रेष्ठ है।

शनि की शांति के लिए

मां काली की उपासना है अचूक

मां काली शक्ति सम्प्रदाय की सबसे प्रमुख देवी हैं, जिस तरह संहार के अधिपति शिव जी हैं उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी मां काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप हैं। शुम्भ-निशुम्भ के वध के समय मां के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। इनकी पूजा उपासना से भय नाश, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। इनकी उपासना से तंत्र-मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। मां काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों, विशेषकर राहु और केतु शनि की शांति के लिए मां काली की उपासना अचूक होती है।

मां काली की पूजा की विशेषता और सावधानियां क्या हैं

सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश के नहीं की जा सकती है। मां काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है।

शुक्रवार के दिन पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर माता के मंदिर में जाकर गुग्गल की धूप जलाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर अपनी समस्याओं के खत्म करने की प्रार्थना करें।

मां काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जो सामान्यत: इन्हें अर्पित की जाती हैं।

मां काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए मां की उपासना नहीं करनी चाहिए।

शत्रु और मुकदमे की समस्या से ऐसे पाएं मां काली की कृपा से मुक्ति

- लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठें।
- मां काली के समक्ष दीपक और गुग्गल की धूप जलाएं।
- मां को प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें।
- शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें।
- मंत्र जाप के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें।
- ये प्रयोग लगातार 27 रातों तक करें।
- माता काली के समक्ष जलाएं दिव्य धूप।
- 11 या 21 शुक्रवार मां कालिका के मंदिर जाएं।
- लाल आसन पर बैठकर मां काली का 108 बार जाप करें।

न्याय के देवता शनि को इस तरह करें खुश

न्याय के देवता शनि हमारे सम्पूर्ण कर्मों का लेखा-जोखा अपने साथ रखते हैं। शनि का श्यामल जैसा रंग, रूप और कठोर व्यवहार देखते ही मन भय से भर जाता है कि कहीं शनि महाराज हमसे रुष्ठ ना हो जाए क्योंकि शनि महाराज सभी मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार दण्डित और पुरस्कृत करते हैं। शनि देव सभी के साथ न्याय करते है पर जो व्यक्ति अनुचित कार्य करते हैं।

परिश्रमी व्यक्ति को मिलता है शनि का आशीर्वाद

शनि महाराज और परिश्रमी व्यक्ति का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। जब कोई मनुष्य श्रम पर ध्यान केन्द्रित करता है और खुद को सदैव स्पष्ट रखता है तो शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके श्रम के अनुसार उसका भाग्य बनाते है। मनुष्य अधिक मेहनत करने पर पसीने से श्याम वर्ण का लगने लगता है। शनि भी श्याम वर्ण के है और सोच-समझ कर धीमी गति से कार्य करते हैं इसीलिए शनि देव का जीवन त्रुटि रहित जीवन जीने को प्रेरित करते हैं।

शनि देव भावनाहीन और न्यायप्रिय है

शनि सूर्यपुत्र और मृत्यु के स्वामी यम के अग्रज हैं। सूर्य के द्वारा तिरस्कार मिलने पर शनि भावना और मन के विपरीत कार्य करते हैं इसलिए न्याय के राजा भी हैं क्योंकि न्यायाधीश को किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। इनका श्याम वर्ण भी इसी बात को सिद्ध करता है कि शनि पर किसी भी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता।

चरित्रवान व्यक्ति पर कुर्बान

शनि देव सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया अर्थात प्रतिबिम्ब के पुत्र हैं। हमारा चरित्र भी छाया की भांति हमेशा हमारे साथ ही रहता है इसलिए शनि देव नेक और छल-कपट से दूर बंदो के साथ हमेशा न्याय करते हैं।

शनि का सफलता प्राप्ति का मंत्र

प्रतियोगिता के इस दौर में शनि देव की शिक्षा हमें जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। आज व्यक्ति के जीवन में सफल होने के बाद भी कोई आंतरिक खुशी नही है क्योंकि सफलता और प्रसिद्धि के लिये अपनाए गए लघुपथ तरीकों से किसी अन्य का अहित भी हो जाता है और यहीं से मनुष्य शनि के न्याय क्षेत्र में प्रवेश करता है इसलिए हमें सफलता के साथ-साथ मानवीय गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए तभी मनुष्य जीवन में सुख-शांति से रह पाता है।

भारतीय शहरों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने का माहौल बनाने की जरूरत : अध्ययन

नयी दिल्ली। एजेंसी

वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के साथ देश की आबादी के मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियों के बढ़ते प्रसार के जोखिम के मद्देनजर एक नए अध्ययन में शहरों में ऐसा वातावरण बनाने की सिफारिश की गई है जो शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दे। अध्ययन के मुताबिक निर्मित माहौल आबादी की शारीरिक गतिविधि के स्तर पर जबर्दस्त प्रभाव डालता है, असंख्य चिरकालिक बीमारियों एवं रोगों को विकलांगता बनने से रोकने और जीवनपर्यंत सेहत को ठीक रखने में मददगार होता है। इसमें कहा गया कि यह वायु प्रदूषण के स्तर, सतह एवं आस-पास के तापमान, कार्बन एवं अन्य जहरीले उत्सर्जनों तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को भी अत्यंत प्रभावित करता है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। 'बिल्ट इन्वायरन्मेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी - एन अर्बन बैरोमीटर, सर्विलांस एंड मॉनीटरिंग' शीर्षक वाले इस शोध में पैदल चलने वालों की प्राथमिकता एवं उनकी गरिमा पर केंद्रित शहरी एवं नागरिक सुविधाओं, पेड़ों की छांव में बने चौड़े रास्ते, पानी के फव्वारे, बुजुर्गों के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बेंच, 0.5 किलोमीटर के दायरे में हरे-भरे हरित क्षेत्रों या शहरी जंगलों तक पहुंच और स्कूलों में बड़े पेड़ों की छांव में बने खेल के मैदान आदि की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कार्य स्थलों पर कसरत के लिए सुविधाएं मुहैया कराने, भवन निर्माण में सीढ़ियों या रैंप को प्राथमिकता देना और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधाओं की जरूरत भी बताई गई। यह अध्ययन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) और सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज कंट्रोल के शोधकर्ताओं ने किया है। यह 'ओबेसिटी रिव्यूज' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

तेज रफ्तार वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

2.37 प्रतिशत बढ़कर 1.51 लाख हुई

देश में 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या एक साल पहले के मुकाबले 2.37 प्रतिशत बढ़कर एक लाख 51 हजार 471 तक पहुंच गईं। इस दौरान कुल मिलाकर चार लाख 67 हजार 044 सड़क दुर्घटनायें हुई। तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और गलत दिशा में गाड़ी चलाना दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह रही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में जितनी जानें गयीं, उनमें सबसे ज्यादा जानलेवा दुर्घटनायें छोटी सड़कों पर हुईं। वहीं करीब 60 प्रतिशत जानें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यस्तरीय सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में गईं। इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन चालक मारे गये। उसके बाद पैदल और साइकिल सवार लोग दुर्घटनाओं के शिकार हुये। वहीं इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 45 आयुवर्ग के लोग रहे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस सालाना रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार वाहन चलाना रहा। तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से 2018 में 64.4 प्रतिशत यानी 97 हजार से अधिक लोगों की मौतें हुई। वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने की वजह से 8,785 लोग (5.8 प्रतिशत) मारे गये। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से 3,635 लोग (2.4 प्रतिशत) और शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से 4,241 (2.8 प्रतिशत) लोगों की दुर्घटना में मौत हुई। बिना वैध लाइसेंस अथवा लर्निंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 13 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण बने। दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में 29 प्रतिशत मौतें हुई। वहीं 16 प्रतिशत मौतों की वजह सीटबेल्ट नहीं पहनना रहा। सड़क दुर्घटनाओं में हुई 41 प्रतिशत मौतों में दस साल से ज्यादा पुराने वाहनों का इस्तेमाल था, वहीं क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाने से 12 प्रतिशत मौतें हुईं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन शोध विभाग द्वारा जारी इस सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज्यादा 30.2 प्रतिशत दुर्घनायें हुई जिनमें 35.7 प्रतिशत लोग मारे गये। वहीं राज्य स्तरीय राजमार्गों पर 25.2 प्रतिशत दुर्घटनाओं में 26.8 प्रतिशत मौतें हुईं। वहीं अन्य सड़कों का कुल दुर्घटनाओं में 45 प्रतिशत हिस्सा रहा और इनमें 38 प्रतिशत लोगों की जानें गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 18 से 45 आयुवर्ग के युवा शिकार हुये हैं। वहीं इन दुर्घटनाओं में 18 से 60 साल आयुवर्ग की बात की जाये तो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों में इस आयुवर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 84.7 प्रतिशत रही। दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 86 प्रतिशत पुरुष और 14 प्रतिशत महिलाओं की जान गई। मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में पिछले साल के मुकाबले मामूली 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक साल पहले 2017 में कुल 4,64,910 दुर्घटनायें हुईं थी, जो कि 2018 में बढ़कर 4,67,044 तक पहुंच गईं। हालांकि, दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में इस दौरान 2.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की संख्या में आलोच्य अवधि में 0.33 प्रतिशत की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार जहां 2010 तक सड़क दुर्घटनाओं, उनमें मरने वालों और घायल होने वालों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही थी, वहीं इसके बाद के वर्षों में यह संख्या करीब करीब स्थिर हो गई और साल दर साल इनमें मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई। वर्ष 2010 से 2018 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की संख्या की मिश्रित सालाना वृद्धि की बात की जाये तो इसमें काफी कमी आई है। सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि के बावजूद पिछले दशकों के मुकाबले यह सबसे कम रही है। सरकार ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाये हैं। सड़कों पर वाहन चलाने के लिये लोगों को शिक्षित करने, वाहनों और सड़कों की बेहतर इंजीनियरिंग और परिवहन विभाग के अधिकारियों की सक्रियता बढ़ाई गई है। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को भी पारित कराया है।

निकट भविष्य में कम नहीं होंगे सोने के दाम: एसबीआई सलाहकार

हैदराबाद। एजेंसी

देश में निकट भविष्य में सोने के दाम नीचे आने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है हालांकि, वाहन उद्योग की संभावनायें उद्योग के लिये किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों पर निर्भर करती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सोमैया कांति घोष ने मंगलवार को यह कहा। घोष ने यहां 'इंस्टीट्यूट फार एडवांस स्टडीज इन कम्पलैक्स च्वाइसेज (आईएएससीसी) के कार्यक्रम में कहा वित्तीय और कंपनी क्षेत्र आज अपनी साख और उतार-चढ़ाव से जूझने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक पटल की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि हार्मुज जलडमरू, कोरियाई द्वीप और ताइवान में सैन्य टकराव की आशंका वैश्विक अर्थव्यवस्था और खासतौर से भारत के लिये किसी भी तरह सकारात्मक नहीं हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चालू वित्त वर्ष के आखिरी छह माह में सोने के दाम लगातार चढ़ते रहें। आने वाले समय में इसकी उम्मीद कम ही लगती है कि सोने के दाम नीचे आयेंगे। इस साल धनतेरस पर सोने का दाम 39,000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया जबकि एक साल पहले इस दिन यह 32,690 रुपये प्रति दस ग्राम पर था। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के मुताबिक मंगलवार को सोना 328 रुपये बढ़कर 39,028 रुपये पर बोला गया।

घोष ने कहा कि कई देशों में गृहकलह के चलते पड़ौसी देशों में शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही भूराजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है जिसका जिंस बाजारों पर प्रभाव पड़ रहा है। एसबीआई सलाहकार ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था बाहरी प्रभावों के असर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसका वृद्धि में आ रही सुस्ती का प्रभाव देखा जा सकता है। उनके मुताबिक भारत सहित कई देशों में जून 2018 के मुकाबले जून 2019 में वृद्धि में 0.22 से लेकर 7.16 प्रतिशत तक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि वाहनों की बिक्री में आई गिरावट आने वाली तिमाहियों में क्या हो सकता है इसका संकेत देती है। इसमें जब तक सुधार के उपाय नहीं होते हैं वृद्धि में नकारात्मक का रुझान दिखाई देता है। अब लोग 10 लाख रुपय से महंगी कारें खरीदने पर ध्यान दे रहे हैं। महिला कार खरीदारों की संख्या बढ़ रही है। इससे देश में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ने का संकेत मिलता है।

वाणिज्य मंत्रालय ने काजू निर्यात संवर्धन परिषद को डंपिंग जांच के लिए आवेदन करने को कहा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य मंत्रालय ने काजू निर्यात संवर्धन परिषद से व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के पास अर्जी देने को कहा है ताकि देश में काजू की डंपिंग के आरोपों की जांच शुरू की जा सके। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि काजू की डंपिंग से घरेलू उत्पादकों पर असर पड़ने की शिकायतें मिल रही हैं। पिछले महीने देश के निर्यात प्रदर्शन पर हुई बैठक में परिषद ने भारत में टुकड़ा काजू की डंपिंग का मामला उठाया था। अधिकारी ने बताया कि भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद से डंपिंग - रोधी जांच के लिए डीजीटीआर के समक्ष अनुरोध दायर करने को कहा गया है। डीजीटीआर किसी उत्पाद के डंपिंग या उसके आताय में भारी वृद्धि से जुड़े मामलों की जांच करती है। डीजीटीआर जांच में यदि यह पता चलता है कि डंपिंग और आयात बढ़ने से घरेलू उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं तो महानिदेशालय डंपिंग - रोधी और रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकता है। इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है। परिषद के चेयरमैन आर . के . भूदेस ने कहा कि गुयाना , मोजाम्बिक , तंजानिया और आइवरी कोस्ट सहित अफ्रीकी देशों से बड़ी मात्रा में अर्द्ध - प्रसंस्कृत काजू की भारत में डंप की जा रही है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये कृषि की बेहतर सूचनाओं की जरूरत- बिल गेट्स

नयी दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि बेहतर सांख्यिकीय सूचनाएं तथा नवोन्मेषी उपायों से कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। उन्होंने कृषि-सांख्यिकी पर 8वें वैश्विक सम्मेलन में यहां कहा कि छोटे किसानों पर आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा। ऐसे में कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिये अवसर बढ़ेंगे तथा वे उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गेट्स ने कहा, ''ऐसे समय में जब हमें उत्पादन बढ़ाना है, जलवायु परिवर्तन इसे मुश्किल बना रहा है।

बदलता मौसम किस तरह से हमारे फसलों और उत्पादकता को प्रभावित करता है, इसे समझने के लिये नये उपायों के इस्तेमाल के साथ कृषि-सांख्यिकी में सर्वश्रेष्ठ कार्यों की जरूरत है।'' उन्होंने भारत के मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि मृदा की गुणवत्ता के आंकड़ों से किसानों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस उर्वरक का इस्तेमाल करें। अभी मौजूदा आंकड़ों के साथ अतिरिक्त आंकड़े जोड़ने तथा विस्तार से मृदा मानचित्रण के अवसर हैं। उन्होंने कहा, ''बेहतर मृदा, बेहतर सूचनाएं और बेहतर सांख्यिकी जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम करने में मदद करेगी।'' गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जटिल है। बीजों की नयी किस्म का विकास तथा किसानों के बीच उनके वितरण समेत विभिन्न प्रकार के दखल की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से छोटे किसान सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये किसान बहुत गरीब हैं और उनके बच्चे कुपोषित हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत में एक मुद्दा है। उन्होंने कहा, ''एक मौसम का सूखा या बाढ़ इन परिवारों की सारी बचत बर्बाद करने के लिये काफी है। आने वाले समय में सूखा और बाढ़ दोनों की आवृत्ति बदलने वाली है। जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा।'' कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, ''भारत कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था है। सरकार को नीति अनाने के लिये आंकड़ों की जरूरत होती है।'' उन्होंने कहा कि भारत में सांख्यिकी का विषय ऐतिहासिक है। मौर्य साम्राज्य के दौरान कौटिल्य के सिद्धांतों में इस बात का विस्तार से वर्णन है कि कृषि, जनसंख्या तथा आर्थिक गणना से संबंधित जानकारियां किस तरह से जुटायी जायें।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

Why Should You
Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019

LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY: Godrej, Bobcat, Reliable Terrestrials, BHAVYA, MB JIGSON, PPPL

CO-SPONSORED BY: PrimePackIndia, SUPREME PEB, WARPP, OSSWAL, JANATICS, Busy

ORGANISED BY: FUTURE COMMUNICATIONS
CONCURRENT EVENT ORGANISED BY: BME
SPONSORED BY: Sanchay Laxmi
SUPPORTED BY: Pumps India Valves India, IMPA, INDIAN FORUM
COMPRESSED AIR PARTNER: Gardner Denver
MEDIA PARTNER: पसार टाइम्स, tradeindia, ENGINEERING REVIEW, Tender247, trade4india
DESIGN PARTNER
BEVERAGE PARTNER
TRANSIT PARTNER: Money4Drive
WEB PARTNER: Creato Web

For Participation Call
9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408
futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।